Shri Hem Barua (Gauhati): May I submit that Shri Nath Pai should withdraw his plea in the face of these disastrous consequences of his advocacy for long questions and answers?

Mr. Speaker: Instead of suggesting it to me, he cou'd have advised his hon. friend Shri Nath Pai.

श्री तु० अ० पाटिल (उस्मानाबाद) : अवर्षण के कारण सारे देश में, ख़ासकर महाराष्ट्र में, अकाल की परिस्थिति निर्माण हुई है, तो क्या इसका सामना करने के लिए सरकार काश्तकारों को सस्ते दामों पर आयल इंजन, खाद और बीज सप्लाई करने की सोच रही है ?

Shri C. Subramaniam: Yes, this is one of the schemes which we have formulated, namely that we should supply oil engines and also supply water at concessional rates, so that whatever water is available can be used beneficially.

(ii) IMPOUNDING OF INDIAN SHIPS AND CONFISCATION OF JUTE, TEA ECT. BY PAKISTAN—*contd.*

Mr. Speaker: Now we shall take up the cal'ing-attention-notice on Impounding of Indian ships and confiscation of jute, tea etc. by Pakistan, which was held over on Friday. Hon. Members may put their questions on it now.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या सरकार वह बता सकती है कि हमारा जो सामान रोका गया है, उसमें हमारा डिफेंस का कितना सामान है ? स्वेज कैनाल की कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो फैसला दिया है, क्या हमने उसके खिलाफ़ अपील इंटरनेशनल कोर्ट में कर दी है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : यह बताना तो कठिन है कि उसमें वास्तविक रूप से कितना डिफ़ेंस का सामान है । जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देने की बात नहीं है । कोर्ट के सामने वह एविडेंस नहीं था, जो कि वह चाहती थी । इस केस में मेन एविडेंस था मैनिफ़ेस्ट, जो बाजे-कराची के कप्तान ने अदालत को नहीं दिया और इस लिए अदालत कोई फ़ैसला करने में मजबूर रही ।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : युद्ध इनाम अदालत (वार प्राईज कोर्ट) की स्थापना करके पाकिस्तान ने यह सिद्ध कर दिया है कि उसने हमारे ख़िलाफ़ इकतरफ़ा युद्ध की घोषणा कर रखी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बात पर ग़ौर किया है कि पाकिस्तान के साथ हुए सभी पुराने समझौतों को—ख़ासकर के नहरी पानी समझौते और कच्छ समझौते को—भंग कर दिया जाये ।

श्री राज बहादुर : इन समझौतों को भंग करने का प्रश्न दूसरा है । किन्तु जहां तक इस प्राईज कोर्ट का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक एक व्यवस्थित ढंग से युद्ध की घोषणा न हो—पाकिस्तानी विधान के अन्तर्गत भी जब तक वह आर्डिनेन्स जारी करके युद्ध की घोषणा न करें—, उस समय तक वह युद्ध घोषित नहीं माना जा सकता और उस समय तक कोई भी प्राईज कोर्ट स्थापित नहीं की जा सकती ।

Shri Alvares (Panjim): After the first and second world wars, the Allied Powers asked for compensation from Germany for illegal seizures of Prize Courts and the damage caused. Because of illegal seizures by Pakistan prize courts and the damage caused, have the Government of India asked for reparations from Pakistan? If not, do they propose to do so?

Shri Raj Bahadur: This question will certainly be taken into account and consideration and in the fu'lness of time, we shall do that. But I may say that so far as the proceedings of

the prize courts are concerned, we hold them as absolutely illegal as per international law, absolutely unconstitutional,....

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Monstrous, atrocious.

Shri Raj Bahadur:.. .even against the constitution of Pakistan and absolutely immoral and uncivilised behaviour.

Shri Alvares: Are Government considering asking for reparations?

Mr. Speaker: That would be taken up when the time comes.

श्री योगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : आ गया है :

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (बिजनौर) मैं जहाजरानी मंत्री के वक्तव्य की एक पंक्ति उन्हीं को सुनाना चाहता हूं : "अन्य क्षेत्रों में अपनी नीति के अनुसार जहाजरानी के क्षेत्र में भी हमने कोई युद्ध की तैयारी नहीं की थी"। सरकार पर इस अकर्मण्यता और उदासीनता का आरोप लगाते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि यद्यपि मंत्री महोदय ने पाकिस्तान के द्वारा रोके गये हमारे सामान के बारे में अलग-अलग आंकड़े दे कर अपने वक्तव्य को बड़ी कुशलता से तैयार किया है, किन्तु क्या वह बता सकेंगे कि पाकिस्तान ने कुल मिला कर हमारा जो सामान रोका है, सामूहिक रूप से उसका अनुमानित मूल्य कितना बैठेगा।

श्री राज बहादुर : जो कुछ मैंने कहा था, उसका मतलब यह है कि भारत पहले से पाकिस्तान पर आक्रमण करने की तैयारी नहीं कर रहा था भारत ऐसा कर रहा है ऐसा तो किसी का भी कहना नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं ने माननीय मंत्री के वक्तव्य की पंक्ति पढ़ कर सुनाई है।

श्री राज बहादुर : पहले पाकिस्तान ने एक युद्ध जैसी कार्यवाही की, जिसका जवाब हमको देना पड़ा। मैं उस वक्तव्य से बंधा हुआ हूं। जहां तक मूल्य का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा है, निश्चित मूल्य नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जानकार हल्कों ने जो कुछ भी अनुमान लगाया है, उस के अनुसार हमारा जो सामान (कारगो) पाकिस्तान के पास है, उसका मूल्य 10 करोड़ रुपये है। उसमें से 7.5 करोड़ रुपये का सामान इन्शोर्ड है और उसमें से भी—और इस इन्शोर्ड में से भी—6.25 करोड़ ऐसा है, जो विदेशी इन्शोरेंस कम्पनियों को देना है। शेष 3.75 करोड़ रुपये के करीब का सामान ऐसा है जो इन्शोरेंस से कवर्ड नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पाकिस्तान ने हमारे जहाज भी रोक रखे हैं।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 19 तटस्थ जहाजों पर भारत का जो माल लदा हुआ था, वह भी पाकिस्तान ने उतार लिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार कर रही है कि भारत का माल पृथक जहाजों पर लादा जाये और पाकिस्तान का माल पृथक लादा जाये, जिस से भारत का माल पाकिस्तान न उतार सके।

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेटमेंट में लिखा हुआ है।

श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़) : यदि सरकार इस प्रकार हमारा माल जब्त किये जाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो क्या वह इस सारे मामले को हेग के इन्टरनेशनल कोर्ट के सामने रखने का विचार रखती है?

श्री राज बहादुर : पाकिस्तान ने इन्टरनेशनल ला का उल्लंघन किया है। इन्टरनेशनल कोर्ट आफ़ जस्टिस का इस मामले में जूरिस्डिक्शन है या नहीं, यह प्रश्न दूसरा है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि 32 लाख 394 टन माल पाकिस्तान ने हमारा उतारा है और हमने 17 लाख 277 टन माल पाकिस्तान का उतारा है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारा जो माल उतारा गया है उसमें कौन-कौन सी वस्तुयें हैं और उनका जो हमने उतारा है उस में कौन कौन सी वस्तुयें हैं और ये दोनों कितनी कीमत के हैं। जो माल आता है वह क्या एक ही जहाज में आता है यदि हां, तो भविष्य में एक ही जहाज में न आये इसके लिये क्या विशेष प्रबन्ध किया गया है? आगे इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि कुछ नाजुक प्रश्न हैं। इनके शब्द ये हैं "इन घटनाओं के कुछ पहलू नाजुक हैं।" मैं जानना चाहता हूं कि कौन से नाजुक पहलू हैं जिनको ये बतलाना नहीं चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : आपको बता दिये तो फिर वे नाजुक कैसे रहे?

श्री हुकम चन्द कछवाय : इतना ही कह कर इसको इन्होंने छोड़ दिया है।

श्री राज बहादुर : पहले तो मैं फिगर्स को ठीक कर दूं। जो हमने डिटेन किया है वह 17,277 टन है और पाकिस्तान ने जो किया है वह 32,394 टन है। जहां तक नाजुक पहलुओं का सवाल है, मैंने कहा है कि पहले तो इंटरनेशनल ला इसमें आता है। दूसरे यह आता है कि बिना युद्ध की घोषणा किये हुए पाकिस्तान ने प्राइज कोर्ट्स बना दीं और फिर कनफिसकेट कर लिया। इसलिये अगर कोई भी दूसरा आदमी इस माल को खरीदता है चाहे विदेशी हो, किसी भी देश का हो, उस खरीद फरोख्त को हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम रिकगनाइज नहीं करेंगे। इस प्रकार का माल जो कोई लेगा वह ठीक वैसे ही होगा जैसे कि स्टोलन प्रापर्टी होती है, चोरी का माल होता है। जैसे चोरी का माल होता है वैसे ही यह माल भी माना जाएगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : कौन-कौन सी वस्तुयें उन्होंने उतारी हैं और कौन कौन सी हमने उतारी हैं और उनका मूल्य क्या है, इसका जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि स्टेटमेंट रख दें।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हमने जो उतारा है उसमें कौन-कौन सी चीजें हैं और कितने मूल्य का है और उन्होंने जो उतारा है, उसमें कौन-कौन सी चीजें हैं और वह कितने मूल्य का है?

अध्यक्ष महोदय : मैं कह दूंगा।

Shri Indrajit Gupta (Calcutta South West): With reference to the efforts that were made by us to persuade neutral ships carrying Indian cargo to come to India and unload that cargo first before proceeding to Pakistan, I want to know whether it is a fact that in respect of a certain Italian vessel, the managing agents of that particular line, who happen to be Messrs. McKinnon, McKenzie & Co., operating in this country, refused to heed this request, though they could have easily done so, and let that vessel go directly to Pakistan instead of coming to India with the result that we lost quite a lot of cargo? If that is so, have the Government taken any steps to convey our displeasure to the right quarters against this sort of anti-Indian activity by British concerns?

Shri Raj Bahadur: I think the facts have been mixed up. Messers McKinnon, McKenzie & Co., were agents for a vessel known as *Steel Vendor* belonging to Isthmian Co. of the United States. The Italian company is Llyod Triestino. We had made a request that the neutral vessels, third party vessels, need not go to Karachi, that they should come to Bombay or our ports first and give up their prescribed scheduled route. Most of the vessels did accept it. There was one vessel, *Steel Vendor,* of Messrs. McKinnon, McKenzie & Co., which came up to Bombay without entering our waters, and then, after just asking for a berth, it went away without indicating its destination and when it would come back. In the particular circumstances, we think that either the company which owns this ship, or its agents, could have prevailed upon it not to go to Karachi and create a situation in which the cargo was lost to us. So, we hold that company responsible for the loss of this cargo and we are asking them to make good this loss as best as they can.

Shri Indrajit Gupta: What about the second part of my question, to see that they do not behave in this manner.

Shri Nath Pai: With impunity very often.

Shri Raj Bahadur: We hold that this company and their agents could have avoided this loss to us, and therefore we have taken serious notice of it.

Shri Nath Pai: Do not take notice, take some action. Do something positive.

Shri Raj Bahadur: We shall take such action as may be justified on merits.

One or two other vessels did not listen to our request deliberately. For instance, the *Isarco* of the Lloyd Triestino went on to Karachi. Another vessel, *Adige,* of that company came to Bombay and the port and dock workers boycotted it.

Shri Nath Pai: That is a very good thing they did. Government should do something like that.

Dr. L. M. Singhvi: Are Government satisfied with the judicial stalemate created by the non-production of the manifest by the Captain of Bagh-e-Karachi, and may I know whether Government took any action or retailiatory measures or remedial measures thereafter in respect of the wanton violation of international maritime law by Pakistan by the constitution of a prize court?

Shri Raj Bahadur: Again there are two questions and my answer has to be a little lengthy. So far as *Bagh-e-Karachi* is concerned there is no question of our being satisfied. It had our cargo under the conference system and we wanted it to be offloaded at a neutral port, Port Said. The court came to our assistance but the British captain of that ship did not co-operate and flouted the order of the court and that ship could not be persuaded to offload our cargo.

So far as the prize court is concerned, I have said that it is an illegal action and we shall recognise no act on its part of confiscation of our goods and any person who deals with such goods will only do so at his own risk and we shall not recognise the transfer of ownership of such goods and any person who posseses such goods is to be regarded as being in possession of stolen property.

Dr. L. M. Singhvi: Mr. Speaker, my quetion was whether at that time government made any efforts to take retaliatory measures against Pakistan vessels or vessels which were on their way to Pakistan? Do government propose to take any remedial steps and if so what are they?

Shri Raj Bahadur: The remedial, steps have been detailed. But for these remedial steps all these 38 neutral ships which carried cargo for Pakistan would have gone on to Pakistan. Of the 19 vessels that went

[Shri Raj Bahadur]

there, eight were already there before the hostilities broke out in the open and only 11 did not care for our persuasion and therefore we lost some of our goods.

Shri Nath Pai: He asked about retaliatory steps.

Mr. Speaker: He gave them in that statement.

Shri Nath Pai: One thing was remedial steps; the other was retaliatory. He detailed the remedial steps in that statement. What about the retaliatory steps, the only language that Pakistan understands.

Shri Raj Bahadur: That also, I submit, is included in the statement.

Mr. Speaker: That is what I am saying again and again.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें। आपने कहा था कि बाद में दिलवा देंगे। पाकिस्तान ने जो माल उतारा है उसमें कौन-कौन सी वस्तुयें हैं और वह कितने मूल्य का है और हमने जो उतारा है उसमें कौन-कौन सी वस्तुएं हैं और वह कितने मूल्य का है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं उनको कह दूंगा कि स्टेटमेंट में वह रख दें। हर एक चीज इस वक्त यहां आ सकती है। सारी चीज अगर रखी जाए तो कितना वक्त इस में लग जाएगा।

Shri Raj Bahadur: May I just say one word about your instructions, Sir? Do you want in that statement complete list of all the cargo that had been offloaded?

Mr. Speaker: If it is not possible he might indicate so in his answer.

Shri Raj Bahadur: It is not possible and it would not also be in public interest.... (*Interruptions.*)

12.38 hrs.

RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES (*Query*).

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री के ब्यान के बाद जितने भी स्थगन अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे थे वे सब ताजा हो जाते हैं। प्रधान मंत्री ने किसी प्रश्न का भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। इसीलिये मैंने आपको पत्र लिखा है कि वे स्थगन तथा ध्यानाकर्षण और जितने भी दूसरे प्रस्ताव हैं, उन्हें आप लेने की कृपा करें। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मै उनके बारे में कुछ कहूं।

अध्यक्ष महोदय : आपसे मैं सिर्फ इतना ही विनय करना चाहता हूं कि मैंने आपकी उस चिट्ठी के आने पर प्रधान मंत्री साहब से पूछा है कि आया कोई डिसकशन वह इस किस्म का ला रहे हैं जिसमें उनको उठाया जा सके। मुझे उनका जवाब आ जाने दीजिये, मैं आपको उत्तर दे दूंगा इस बात का। मुझे पता लग जाने दीजिये कि कौन सा डिसकशन आ रहा है। अगर यह चीज उसमें कवर नहीं होती है तो मैं सोचूंगा।

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Sir, I had requested you to fix a date for the discussion of the statement made by the Prime Minister here that day.

Mr. Speaker: That is what I am submitting. I have asked the Prime Minister whether government is making any motion. I find it difficult to say that the PM's statement should be discussed. It should be put in some other form. I have made enquiries and let me have that information. Then we will see in what shape or form we can have it.